ISSN 2277-5897 SABLOG
PEER REVIEWED JOURNAL

151

लोक चेतना का राष्ट्रीय मासिक

सबलोग

सितम्बर 2026 • ₹ 50

शिक्षा के सौदागरों से सवाल

- इक्कीसवीं सदी का आईना हैं भारतेन्दु
- संसद के भीतर और बाहर का दृश्य
- बांकीपुर का जनादेश और प्रशांत किशोर

सबलोग-151

वर्ष 17, अंक 9, सितम्बर 2026

ISSN 2277-5897 SABLOG

PEER REVIEWED JOURNAL

www.sablog.in

सम्पादक

किशन कालजयी

संयुक्त सम्पादक

प्रकाश देवकुलिश

राजन अग्रवाल

उप-सम्पादक

गुलशन चौधरी

समीक्षा समिति

(Peer Review Committee)

आनन्द कुमार

रत्नेश्वर मिश्र

मणीन्द्र नाथ ठाकुर

मंजु रानी सिंह

सफदर इमाम कादरी

प्रमोद मीणा

राजेन्द्र रवि

मधुरेश

महादेव टोप्पो

विजय कुमार

आशा

सन्तोष कुमार शुक्ल

अखलाक 'आहन'

अभय सागर मिंज

सम्पादकीय सम्पर्क

बी-3/44, तीसरा तल, सेक्टर-16,
रोहिणी, दिल्ली-110089

+918340436365

sablogmonthly@gmail.com

सदस्यता शुल्क

एक अंक : 50 रुपये

वार्षिक : 1100 रुपये रजिस्टर्ड डाक से

सबलोग

खाता संख्या-49480200000045

बैंक ऑफ बड़ौदा,

शाखा-बादली, दिल्ली

IFSC-BARB0TRDBAD

(Fifth Character is Zero)

स्वामी, सम्पादक, प्रकाशक व मुद्रक किशन कालजयी द्वारा बी-3/44, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089 से प्रकाशित और लक्ष्मी प्रिण्टर्स, 556 जी.टी. रोड शाहदरा दिल्ली-110032 से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, उनसे सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं।

पत्रिका अव्यावसायिक और सभी पद अवैतनिक।

पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली।

संवेद फाउण्डेशन का मासिक प्रकाशन

शिक्षा के सौदागरों से सवाल

मुनादी / सड़क पर उतरता देश और प्रतिरोध की नयी संस्कृति : **किशन कालजयी** 3

नवउदारवाद और शिक्षा का नया संकट : **मणीन्द्र नाथ ठाकुर** 5

सभ्यता के आईने में शिक्षा : **विजय कुमार** 8

योग्यता, बाजार और परीक्षा का विषैला तन्त्र : **मनीष जैन** 11

वंचितों से दूर होती शिक्षा : **राजाराम भादू** 13

पॉलो फ्रेरे की संवादात्मक शिक्षा प्रणाली : **अनिल राय** 15

शिक्षा का निजीकरण और विश्वविद्यालय : **राम नरेश राम** 17

शिक्षा, लोकतन्त्र और नागरिकता का संकट : **रमाशंकर सिंह** 19

सृजनलोक

आठ कविताएँ : **जनमेजय,** टिप्पणी : **श्रीधर करुणानिधि,** रेखांकन : **प्रीतिमा वत्स** 22

देश

बिहार / बांकीपुर का जनादेश और प्रशांत किशोर : **कुमार कृष्णन** 24

झारखण्ड / लोकतन्त्र का खतरनाक संकट है नियुक्ति घोटाला : **सुधीर पाल** 26

हरियाणा / हरियाली के नीचे सूखता पानी : **अजय सिंह** 29

स्तम्भ

चतुर्दिक / संसद के भीतर और बाहर का दृश्य : **रविभूषण** 31

तीसरी घण्टी / मंच पर चार्वाक का प्रवेश : **राजेश कुमार** 34

यत्र-तत्र / सूचना और कल्पना की कीमियागीरी : **जय प्रकाश** 37

देशान्तर / फिलिस्तीनी समस्या–एक अन्तहीन अँधेरी सुरंग : **धीरंजन मालवे** 40

परती परिकथा / इतिहास, खेल और राष्ट्रीय स्मृति : **हितेन्द्र पटेल** 43

विविध

शहरनामा / शहरों ने छीना फुटपाथ : **राजेंद्र रवि** 46

साहित्य / इक्कीसवीं सदी का आईना हैं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : **मृत्युंजय श्रीवास्तव** 48

जयन्ती / लोकतन्त्र, पत्रकारिता और राष्ट्रकवि दिनकर : **अनुज** 50

जन-गण-मन / शिक्षा का बर्बादीकरण और प्रतिरोध : **सर्वेश कुमार मौर्य** 52

सिनेमा / अधूरी मोहब्बत का पूरा वादा : **आशा** 55

किताब / विचारधारात्मक सेवा की सशक्त पहल : **रत्नेश सिन्हा** 57

लिये लुकाठी हाथ / मोबाइल-उपवास : **गिरीश पंकज** 58

रंगसाज / आदिवासी कला, स्मृति और प्रतिरोध की दृश्य-भाषा : **शेखर** 59

आवरण : शशिकान्त सिंह

अक्षर संयोजन : आशीष कुमार पाठक

अगला अंक : नयी पीढ़ी और नया भारत

सड़क पर उतरता देश और प्रतिरोध की नयी संस्कृति

हाल के दिनों में देश में प्रतिरोध के कई रूप सामने आये हैं। कभी परीक्षा और भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे, कभी नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं ने सरकार को घेरा और कभी आरक्षण तथा शिक्षा के सवालों पर प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं को अलग-अलग करके देखने के बजाय एक व्यापक परिघटना के रूप में देखे जाने की जरूरत है। देश में प्रतिरोध की एक नयी संस्कृति विकसित हो रही है, जिसमें युवा अपने भविष्य को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। यह बदलाव किसी खास विचारधारा के प्रभाव में या केवल किसी एक सरकार अथवा राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। सरकार एनडीए की हो या यूपीए की, केन्द्र की हो या राज्य की–जहाँ युवाओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ वे सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

आज से कुछ समय पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश के मुँह से निकला एक शब्द सोशल मीडिया पर प्रतिरोध का रूपक बन जाएगा। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका आशय बेरोजगारों से वह शब्द जोड़ना नहीं था, लेकिन तब तक वह शब्द सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका था। प्रतिक्रिया में अमेरिका में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र द्वारा बनाये गये एक ऑनलाइन समूह ने भी देखते-देखते व्यापक समर्थन हासिल किया। इसके बाद धरना-प्रदर्शन, आन्दोलन और हड़ताल जैसी कार्रवाइयाँ सामने आयीं और बहस शिक्षा तथा रोजगार की व्यवस्था से होते हुए सरकार की जवाबदेही तक पहुँची। यह सिलसिला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। झारखण्ड में प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का आन्दोलन लम्बा चला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी विद्यार्थी और अभ्यर्थी अपनी माँगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते दिखाई दिये। यहाँ तक कि छोटे स्कूली विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शनों को भी सरकारों को सुनना पड़ा। यह बदलाव महत्त्वपूर्ण है।

नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर हुआ आन्दोलन इस बदलते माहौल का एक प्रमुख उदाहरण है। मई 2026 में आयोजित नीट परीक्षा को लेकर प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा-व्यवस्था में अनियमितताओं के आरोप सामने आये। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की निगरानी और नियन्त्रण व्यवस्था पर सवाल उठे। यह सवाल इसलिए भी गम्भीर था कि इससे पहले भी नीट परीक्षा को लेकर विवाद और घोटाले सामने आ चुके थे। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न है कि पिछली घटनाओं से सबक लेने के बाद भी परीक्षा-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार क्यों नहीं हुआ?

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखा। समिति उनके जवाब से सन्तुष्ट हुई और उन्हें पद पर बने रहने दिया गया। लेकिन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के असन्तोष को इससे विराम नहीं मिला। जन्तर-मन्तर पर हुआ आन्दोलन धीरे-धीरे व्यापक युवा असन्तोष का रूप लेने लगा। कई सप्ताह तक चले विरोध ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा। अन्ततः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री के इस्तीफे की माँग आन्दोलन का प्रमुख मुद्दा बन गयी और परीक्षा-व्यवस्था में सुधार तथा कड़े कानूनों की जरूरत राष्ट्रीय बहस के केन्द्र में आ गयी। इस घटना का महत्त्व केवल इतना नहीं है कि एक मन्त्री के इस्तीफे की माँग उठी या सरकार पर दबाव बना। इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि देश के नौजवानों में यह विश्वास पैदा हुआ कि वे संगठित होकर सत्ता को जवाबदेह बना सकते हैं। जिस युवा को अक्सर राजनीति से दूर, मोबाइलजीवी मानते हुए सिर्फ अपने भविष्य की चिन्ता करने वाला माना जाता है, उसने सड़क पर उतरकर बता दिया कि उसके लिए शिक्षा, परीक्षा और रोजगार भी राजनीतिक प्रश्न हैं।

एक विद्यार्थी वर्षों तक तैयारी करता है। जेवर, जमीन बेचकर या भारी ब्याज पर कर्ज लेकर महँगी कोचिंग और रहने-खाने का खर्च उठाया जाता है। कई विद्यार्थी दूसरी सम्भावनाएँ छोड़कर किसी एक परीक्षा की तैयारी में अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा की विश्वसनीयता ही सन्दिग्ध हो जाए तो उसके सामने क्या बचता है? उसकी मेहनत, समय और आर्थिक संसाधन सब एक साथ व्यर्थ हो जाते हैं। सरकारी नौकरी के कुछ हजार पदों के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने, परिणाम रुकने या परीक्षा रद्द होने का अर्थ उनके लिए केवल प्रशासनिक देरी नहीं है। उम्र निकल रही होती है, परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा होता है और कई वर्षों की तैयारी अनिश्चितता में बदल जाती है। इसलिए परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले युवक को केवल 'नौकरी चाहने वाला' युवक समझना उसके असन्तोष की गहराई को न समझना है।

नीट के अलावा बारहवीं की सीबीएसई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर भी गम्भीर सवाल उठे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का ठेका ऐसी एजेंसी को दिये जाने का आरोप है जिसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। इसके लिए सेवा-शर्तों में बदलाव किये जाने और उच्चस्तरीय तकनीकी व्यवस्था के स्थान पर मोबाइल कैमरों के माध्यम से मूल्यांकन की अनुमति दिये जाने की बात भी सामने आयी। राँची के एक छात्र सिद्धान्त जायसवाल ने व्यवस्था में मौजूद कुछ खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसकी बातों की गम्भीरता को देखते हुए उसे मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति के समक्ष बुलाया गया, जहाँ उसने अपने दावों का विस्तार से विवरण दिया। इसी तरह उत्तर पुस्तिकाओं के डेटा लीक होने की सूचना भी सामने आयी। 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी, जो स्वयं को एथिकल हैकर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी।

एक अन्य मामले में छात्र वेदान्त को पुनर्मूल्यांकन के लिए पदार्थ विज्ञान की जो उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी, उसमें उसके द्वारा लिखे गये उत्तर नहीं थे। उसने इस सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर जानकारी दी और बाद में दूसरे विद्यार्थियों ने भी ऐसी ही शिकायतें सामने रखीं। इन घटनाओं की जाँच और उनके निष्कर्ष जितने महत्त्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्त्वपूर्ण है परीक्षा-व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल। यदि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला करने वाली संस्थाओं के बारे में लगातार सन्देह पैदा होता रहे और शिकायतों का समाधान पारदर्शी ढंग से न हो, तो व्यवस्था के प्रति भरोसा कैसे कायम रहेगा?

झारखण्ड का हाल का घटनाक्रम इस व्यापक बेचैनी का दूसरा